



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

09 चैत्र 1944 (श०)

(सं० पटना 137) पटना, बुधवार, 30 मार्च 2022

सं० पि०व०/पो०मै०छा०-36-10/2017-730  
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

संकल्प

28 मार्च 2022

विषय :-पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति हेतु संचालित योजनाओं- केन्द्र प्रायोजित अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना, राज्य योजना के तहत संचालित मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना/मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 की छात्रवृत्ति हेतु एक साथ प्राप्त किये गये आवेदनों को वैधता प्रदान किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में निर्गत आय प्रमाण-पत्र की वैधता को मात्र इस कार्य हेतु विस्तारित किये जाने तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 में निर्गत आय प्रमाण-पत्र को वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 के लिए भी वैध तथा संदर्भित वर्षों के लिए निर्धारित आय अधिसीमा के अधीन मानते हुए मात्र इस कार्य हेतु विभागीय संकल्प सं०-321, दिनांक- 05.02.2019, विभागीय संकल्प संख्या-291 दिनांक-31.01.2020 तथा विभागीय संकल्प सं०-1295, दिनांक-16.08.2021 को इस हद तक यथासंशोधित करते हुए अनुमान्य किये जाने की स्वीकृति।

राज्य के अन्दर एवं राज्य के बाहर देश के अन्दर प्रवेशिकोत्तर कक्षा में अध्ययनरत् पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के प्रतिभावान छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए केन्द्र प्रायोजित अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना संचालित है। इस योजना के तहत विधिवत मान्यता प्राप्त महाविद्यालय, विश्वविद्यालय/शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति की स्वीकृति दी जाती है। इस योजना के तहत राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा राशि उपलब्ध करायी जाती है।

2. विभागीय संकल्प संख्या-291 दिनांक-31.01.2020 द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना से अनाच्छादित रु० 1.50 लाख से अधिक एवं रु० 2.50 लाख मात्र तक की वार्षिक आय अधिसीमा के तहत अर्हता रखने वाले अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर पर छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 से "मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना" की स्वीकृति प्रदान की गई थी। केन्द्र प्रायोजित अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत निर्धारित वार्षिक

आय अधिसीमा वित्तीय वर्ष 2020-21 से ₹0 2.50 लाख किये जाने के फलस्वरूप मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना से अच्छादित छात्र/छात्राएँ भी इस योजना में पात्र हो गये। फलस्वरूप मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना को विस्तारित कर विभागीय संकल्प संख्या-1385 दिनांक-25.08.2021 द्वारा केन्द्र प्रायोजित अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना से अनाच्छादित ₹0 2.50 लाख से अधिक एवं ₹0 3.00 लाख मात्र तक की वार्षिक आय अधिसीमा के तहत अर्हता रखने वाले पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 से “मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना” की स्वीकृति प्रदान की गई है।

3. उक्त प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजनाओं का क्रियान्वयन शिक्षा विभाग के माध्यम किया जा रहा है।

4. पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 का क्रियान्वयन NIC के सहयोग से राज्य स्तर पर विकसित PMS Portal के माध्यम से किया जा रहा है।

5. पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिए प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति हेतु केन्द्र प्रायोजित अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत विभागीय संकल्प सं०-321, दिनांक-05.02.2019 के द्वारा वित्तीय वर्ष-2018-19 से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-**No.11014/31/2017-BC-1** दिनांक-18.09.2018 द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के लिए निर्गत मार्गदर्शिका के आलोक में छात्रवृत्ति देने की स्वीकृति प्रदान की गई है। जिसके अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष-2018-19 से अधिकतम पारिवारिक वार्षिक आय अधिसीमा ₹0-1.00 लाख (₹0 एक लाख) मात्र को बढ़ाकर ₹0-1.50 लाख (₹0 एक लाख पचास हजार) मात्र पुनर्निर्धारित किया गया है।

6. विभागीय संकल्प सं०-1295, दिनांक-16.08.2021 के द्वारा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-**No.12013/03/2020-BC-1** दिनांक-17.07.2020 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2020-21 से अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत अधिकतम पारिवारिक वार्षिक आय अधिसीमा ₹0 1.50 लाख (₹0 एक लाख पचास हजार) मात्र को बढ़ाकर ₹0 2.50 लाख (₹0 दो लाख पचास हजार) मात्र वार्षिक पुनर्निर्धारित किये जाने की स्वीकृति दी गई है।

7. पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 का क्रियान्वयन NIC के सहयोग से राज्य स्तर पर विकसित PMS Portal के माध्यम से किया जा रहा है।

8. पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिए प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति हेतु केन्द्र प्रायोजित अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना एवं राज्य योजना के तहत संचालित मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना/मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 के लिए वार्षिक आय सीमा अलग-अलग निर्धारित किया गया है।

9. वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 का आवेदन एक साथ वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 में PMS Portal के माध्यम से प्राप्त आवेदनों के आलोक में छात्रवृत्ति प्रदान किये जाने क्रम में आय प्रमाण पत्र की वैधता के संदर्भ में निम्नांकित तथ्य परिलक्षित हुए:-

i. कुछ अभ्यर्थियों ने वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में आय प्रमाण पत्र बनवाया था किन्तु एक वर्ष के उपरान्त आय प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त हो चुकी है, और उसी आय प्रमाण पत्र के आधार पर ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

ii. कुछ अभ्यर्थियों का आय प्रमाण पत्र वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में निर्गत नहीं है, लेकिन उनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में निर्गत आय प्रमाण पत्र के आधार पर ऑनलाईन आवेदन किया गया है, जो विभाग द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए निर्धारित आय सीमा के अधीन है। किन्तु वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 के लिए विभाग द्वारा निर्धारित आय सीमा के अधीन नहीं है।

10. उपर्युक्त के आलोक में पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति हेतु संचालित योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 की छात्रवृत्ति हेतु एक साथ प्राप्त आवेदनों को वैधता प्रदान किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में निर्गत आय प्रमाण-पत्र की वैधता को विस्तारित किये जाने तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 में निर्गत आय प्रमाण-पत्र को वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 के लिए भी वैध तथा संदर्भित वर्षों के लिए निर्धारित आय अधिसीमा के अधीन मानते हुए अनुमान्य किये जाने हेतु मात्र इस कार्य के लिए विभागीय संकल्प सं०-321, दिनांक-05.02.2019, विभागीय संकल्प संख्या-291 दिनांक-31.01.2020 तथा विभागीय संकल्प सं०-1295, दिनांक-16.08.2021 को इस हद तक संशोधित किये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन था।

11. अतः सम्यक विचारोपरान्त पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति हेतु संचालित योजनाओं- केन्द्र प्रायोजित अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना, राज्य योजना के तहत संचालित मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना/मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 की छात्रवृत्ति हेतु एक साथ प्राप्त किये गये आवेदनों को वैधता प्रदान किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में निर्गत आय प्रमाण-पत्र की वैधता को मात्र इस कार्य हेतु विस्तारित किये जाने तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 में निर्गत आय प्रमाण-पत्र को वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 के लिए भी वैध तथा संदर्भित वर्षों के लिए निर्धारित आय अधिसीमा के अधीन मानते हुए मात्र इस कार्य हेतु विभागीय संकल्प सं०-321, दिनांक- 05.02.2019, विभागीय

संकल्प संख्या-291 दिनांक-31.01.2020 तथा विभागीय संकल्प सं०-1295, दिनांक-16.08.2021 को इस हद तक यथासंशोधित करते हुए अनुमान्य किये जाने की स्वीकृतिप्रदान की जाती है।

12. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक-23.03.2022 को मद संख्या-09 में स्वीकृति प्राप्त है।

**आदेश:**—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी हेतु बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित कराया जाय और इसकी प्रति सभी संबंधित विभाग/पदाधिकारी एवं कार्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु उपलब्ध करायी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
पंकज कुमार,  
प्रधान सचिव।

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 137-571+10-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>